62वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड की उप राजधानी दुमका में महामहिम का अभिभाषणः–

झारखंड के प्यारे भाईयों, बहनों एवं बच्चों जोहार !

62वें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ । राष्ट्रीय पर्व की इस सुखद बेला में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी और अन्य महान् विभूतियों के साथ झारखंड के अमर शहीद बिरसा मुण्डा, सिदो, कान्हू, नीलांबर, पीताम्बर, चाँद, भैरव, शेख भिखारी, टिकैत उमराँव सिंह, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, पांडेय गणपत राय समेत मैं उन सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों के प्रति भी अपने हृदय की गहराई से सम्मान व्यक्त करता हूँ, जिनके त्याग और बलिदान के कारण ही हमारा देश अंग्रेजी दासता से मुक्त

हुआ तथा आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र व आज़ाद मुल्क के नागरिक कहलाते हैं।

इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं परमवीर चक्र विजेता लांसनायक अल्बर्ट एक्का, कारगिल युद्ध के अमर शहीद नागेश्वर महतो समेत उन सभी वीर सैन्य कर्मियों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपने वतन व मुल्क की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अपनी जान की परवाह कभी नहीं की और देश की संप्रभुता, अखंडता व एकता की रक्षा के लिए अपना तन–मन सब न्यौछावर कर दिया ।

आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी दासता से मुक्त हुआ तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरा था । आज़ादी के वक्त हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्व0 जवाहरलाल नेहरू ने कहा था– इस आधी रात को जब सारा विश्व सो रहा होगा, भारत जागेगा, एक नयी

अंगड़ाई और जज़्बे के साथ । पिछले 61 वर्षों में हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में तरक्की की है, उल्लेखनीय प्रगति की है एवं अपनी चमक दुनिया में बिखेरी है । आज सारा विश्व हमें सम्मान की दृष्टि से देख रहा है । राष्ट्र की इन उपलब्धियों में हमारे राज्य की भी अहम् भागीदारी है । आज हम सबके लिए मनःचिन्तन का अवसर है, आत्म–अवलोकन व आत्म–मंथन का अवसर है कि हमने आजादी के पिछले 61 वर्षों में अपने स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा स्थापित सिद्धान्तों एवं परिकल्पनाओं, उनके द्वारा राष्ट्र व उसके नागरिकों के लिए देखे गये सपनों, उम्मीदों पर कितने खरे उतरे हैं, उन्हें साकार करने एवं मूर्तरूप प्रदान करने कितने सफल हो सके हैं ।

प्रिय राज्यवासियों, हमने कई उपलब्धियाँ अर्जित की हैं, लेकिन आज भी हमारे समक्ष कई चुनौतियाँ हैं, जिसका

सामना हम सबको मिलकर करना होगा । देश की आज़ादी के वक्त पं0 जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि **''अभी हमें मीलों चलना है ।''** आज हम सबको संकल्प लेना होगा कि हम पूरे जोश और विश्वास के साथ सबको साथ लेकर तेज़ी से आगे बढें । आज हमारे समक्ष शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचे की मज़बूती, कार्य संस्कृति का विकास और गरीबों के उत्थान जैसे कई अहम मुद्दे हैं, जिन पर हमें अभी बहुत काम करना है, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है ।

प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हमारे राज्य में बहुमुखी विकास की अनंत संभावनाएँ हैं । 15 नवंबर सन् 2000 को हमारे राज्य की स्थापना हुई थी । प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित इस राज्य में देश की चालीस फीसदी से अधिक खनिज संपदा मौजूद है, तरक्की के लिए बस आवश्यकता है कि हम सब मिल–जुलकर, योजनाबद्ध तरीके से

विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ें । ऐसा करने से ही हमारा एवं हमारे राज्य का सर्वांगीण विकास का सपना पूरा होगा ।

विश्व प्रतियोगिता के इस दौर में आज हम तब तक इस देश को एवं अपने इस राज्य को विश्व के मानचित्र पर स्थापित नहीं कर पायेंगे, जब तक हम लोग शिक्षित नहीं हो जायें। आज प्रत्येक नागरिक को यह समझना होगा कि देश को यदि शक्ति सम्पन्न होना है अथवा बनाना है तो उसे अपनी युवा शक्ति को शिक्षित तथा ज्ञानवान बनाने की शर्त को पूरा करना होगा क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है, वर्तमान में हमारी आबादी के 35 प्रतिशत से अधिक लोग युवा है । वर्ष 2025 तक हमारे देश में 60 फीसदी से अधिक की आबादी युवा वर्ग की होगी और 2050 तक हमारी आबादी का अधिसंख्य हिस्सा युवा वर्ग का होगा । हमें अपनी इस युवा आबादी को बोझ

न समझकर इसे एक बेशकीमती मानव संसाधन, एक अद्वितीय रिर्सोस मानते हुए ऐसे कार्यक्रम चलाने होंगे, जिससे युवा शक्ति को एक नई दिशा मिल सके ।

सन् 2010 तक राज्य की 85 प्रतिशत आबादी को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस दिशा में कई प्रयास किये जा रहे हैं । राज्य में स्कूल नहीं जानेवाले बच्चों की संख्या में विगत कुछ वर्षों में काफी कमी आई है। इसके लिए राज्य में **'सर्वशिक्षा अभियान'** व **'स्कूल चले अभियान'** के अंतर्गत सभी ग्रामों/टोलों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा 6–14 आयु–वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन, विद्यालयों के आधारभूत संरचनाओं का विकास एवं समुदाय के सशक्तीकरण पर बल दिया जा रहा है । बच्चों को विद्यालय तक लाने एवं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मध्याह्न भोजन योजना को कक्षा 8 तक

विस्तारित किया गया है । इससे राज्य के लगभग 37 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी कोटि के वर्ग 1 से 7 तक के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें भी वितरित की गयी है । सरकार द्वारा 5 हजार 604 छात्र–छात्राओं को 2 हजार प्रति छात्र–छात्रा की दर से निर्धनता–सह–मेधा छात्रवृत्ति प्रदान की गई । सरकार द्वारा जनजातियों के विशेष विकास हेतु राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रत्येक जिले में एक–एक आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई होगी एवं इन विद्यालयों में 70 प्रतिशत छात्र–छात्राएं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति वर्ग के होंगे । शिक्षा के व्यापक प्रसार हेतु सरकार द्वारा राज्य में प्रत्येक 5 किलोमीटर की परिधि में एक माध्यमिक विद्यालय एवं 8 किलोमीटर की परिधि में एक प्लस टू

विद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है ।

छात्राओं को शिक्षित करने के दृष्टिकोण से सरकार ने मध्य एवं माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग 8 में पढ़नेवाली 5 हजार 71 बी0पी0एल0 परिवार की छात्राओं को साईकिल का निःशुल्क वितरण किया है । छात्राओं को परीक्षा शुल्क एवं पंजीयन शुल्क से भी मुक्त रखा गया है । विश्वविद्यालयों में भी निःशुल्क बालिका शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों को राशि उपलब्ध कराई गयी है ।

राज्य में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए इस वर्ष 8 हजार 7 सौ 67 सामान्य शिक्षकों एवं 401 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है । इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा बेराजगारों को प्रशिक्षित शिक्षक की श्रेणी में लाने के उद्देश्य से जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 9 से बढ़ाकर 17 की गयी है ।

प्रिय झारखंडवासियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार हेतु कई कदम उठाये हैं । कुलाधिपति होने के नाते मैं प्रत्येक तीन माह में राजभवन, राँची में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों व पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करता हूँ एवं बदलते परिवेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर परिचर्चा करता हूँ । राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले व्यक्तियों का औसत बहुत कम है, हमें इसमें इजाफा लाना होगा । इसी उद्देश्य से हमने राजभवन, राँची में कुलपतियों के साथ पिछली समीक्षा बैठक में उन्हें अपने यहाँ 10 से 15 फीसदी नामांकन सीट बढ़ाने का निदेश दिया था, जिनका उन्होंने बखूबी से पालन किया । आज राज्य के विश्वविद्यालयों के सत्र नियमित चल रहे हैं, सीनेट और सिन्डिकेट की बैठकें नियमित समय पर हो रहे हैं । छात्र–संघ के चुनाव सफलतापूर्वक

सम्पन्न कराये गये, जो पिछले कई वर्षों से लम्बित थे । आज भूमण्डलीकरण के इस युग में लोगों में रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देने की कई योजनाएं बनायी गयी है, ताकि हमारे युवा विश्व की चुनौती के अनुरुप राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के विभिन्न रोजगारों में अपनी जगह बना सकें । शिक्षा उनके लिए न केवल नौकरी प्राप्त करने का जरिया हो, बल्कि उनके लिए स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनने का माध्यम भी बने । इसी उद्देश्य से सभी विश्वविद्यालयों में वोकेशनल पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहे है । राज्य में इंजीनियरिंग, मेडिकल, कृषि आदि तकनीकी शिक्षा के लिए नये महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है, ताकि हमारे नौजवानों को तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु बाहर नहीं जाना पड़े । राज्य में पत्रकारिता के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम शुरु कर युवा–वर्ग को लाभ पहुँचाने हेतु जनसंचार

संस्थान स्थापित करने की ओर राज्य सरकार प्रयासरत है । राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य के दो प्रमण्डलों पलामू एवं कोल्हान में नये विश्वविद्यालय जल्द ही मूर्त रुप में दिखेगें । मुझे आशा है कि इन नये विश्वविद्यालयों की स्थापना से निश्चित रुपेण राज्य के दूर–दराज के इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की नयी किरण व अलख जलेगी । इसके लिए आधारभूत संरचनाओं एवं आवश्यकताओं पर भी समुचित ध्यान दिया जा रहा है ।

प्रिय झारखण्डवासियों, आप सबको यह जानकर बहुत खुशी हो रही होगी कि केन्द्र सरकार द्वारा हमारे राज्य में उच्च शिक्षा में विकास हेतु राज्य में आई0आई0एम0जैसे उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान शुरू करने के प्रयास किये जा रहे हैं । उच्च शिक्षा को व्यापक बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा की सहज पहुँच सुदूर एवं

जनजातीय क्षेत्रों में भी सभी जन–सामान्य को हो, इस उद्देश्य से 50 से अधिक महाविद्यालयों को नव सम्बन्धन/स्थायी सम्बन्धन एवं सम्बन्धन दीर्घाकरण प्रदान किया गया है । मेरे विचार से जहाँ उच्च शिक्षा के दायरे को बढ़ावा देना चाहिए, वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा में निरंतर गुणवत्ता बनाये रखना भी जरुरी है । इसके लिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता बरकरार रखी जाय और विश्वविद्यालयों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे अपने अन्दरुनी संस्थाएँ सीनेट, सिन्डिकेट और एकेडमिक कौन्सिल आदि की बैठक न केवल नियमित करें, बल्कि उसे मजबूती से जीवन्त भी रखें । राज्य के तीन विश्वविद्यालयों में 7 सौ 67 व्याख्याताओं की नियुक्ति की गयी है, ताकि उच्च शिक्षा में पठन–पाठन की व्यवस्था और भी सुदृढ़ हो सकें ।

खनिज सम्पदा से परिपूर्ण झारखंड राज्य में उद्योगों के विकास की असीम संभावनाएँ हैं । यह सर्वविदित है कि किसी भी राष्ट्र अथवा राज्य के उन्नति में वहाँ स्थापित उद्योगों की अहम भूमिका होती है, चाहे वह बड़े उद्योग–धंधे हों या कुटीर उद्योग अथवा लघु उद्योग । भूमण्डलीकरण के इस युग में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गयी है । स्वाधीनता प्राप्ति के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में देश में कई बड़े उद्योग–धंधे स्थापित हुए क्योंकि पंडित नेहरू जानते थे कि बिना औद्योगिकरण के देश का अपेक्षित विकास संभव नहीं है । उद्योग–धंधे श्रमशक्ति के लिए रोजगार के नये द्वार भी खोलते हैं अथवा उद्योगों की स्थापना से रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे, जिससे विस्थापन की समस्या का भी मानवीय हल बहुत हद तक समाधान किया जा सकता है । इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने

ऐसी नीति बनायी है जिसके अन्तर्गत बड़े, मध्यम एवं लघु उद्यमियों का रुझान इस राज्य की ओर बढ़ा है । 67 मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना हेतु किये गये एम0ओ0यू0 से 283 लाख करोड़ रुपये के पूँजी निवेश एवं 2 लाख 50 हजार व्यक्तियों का नियोजन संभावित है । इन एम0ओ0यू0 में से नौ कम्पनियों के द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है जिसमें लगभग 686 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश हुआ है तथा 2 हजार से अधिक लोगों को नियोजन प्राप्त हुआ है । मध्यम श्रेणी की ग्यारह कम्पनियों के द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया गया है, जिनमें लगभग 76 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश हुआ है एवं 825 लोगों को नियोजन प्राप्त हुआ है । खनिजों के दोहन और राज्य के औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण एवं एम0ओ0यू0 किये हुए उद्यमियों को जमीन उपलब्ध कराने हेतु झारखंड औद्योगिक

आधारभूत संरचना विकास निगम (जिडको) का गठन किया गया है । इसके अतिरिक्त राज्य में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण एवं इसके विकास के लिए झारखंड आधारभूत संरचना विकास निगम (जिनफ्रा) का भी गठन किया गया है । विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों के माध्यम से भी उद्यमियों को भी हरसंभव सहायता प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं । हाल ही में, 22 अप्रैल 2008 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने बोकारो में तीसरी धमनभट्ठी की आधारशिला रखते हुए कहा कि खनिज सम्पदा से परिपूर्ण यह राज्य यदि योजनाबद्ध तरीके से कार्य करे तो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने से इसे दुनिया की कोइ ताकत नहीं रोक सकती है । प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण इस राज्य के लिए की जानेवाली विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं से विस्थापित होनेवाले स्थानीय लोगों के लिए

समुचित मुआवजों के साथ विकास के पक्रिया में भागीदारी बनाने के उद्देश्य से झारखंड राज्य पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास नीति, 2008 लागू की गयी है जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है। आशा है कि इससे राज्य में पूँजी निवेश को और बढ़ावा मिलेगा।

स्वास्थ्य सुविधाओं की आधारभूत संरचना का जनसंख्या की समानुपातिक विकास, हमारे राज्य के लिए अहम चुनौती है। सरकार की यह योजना है कि अगले पाँच वर्षो में सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं का इस प्रकार उत्क्रमण/विकास इस प्रकार हो, जिससे इन सुविधाओं से सभी वाँछित स्वास्थ्य सेवाओं लोगों को मुहैया करवायी जा सकें । मातृ एवं शिशु मृत्यु–दर में कमी लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जननी शिशु स्वास्थ्य योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत महिलाओं को सुरक्षित संस्थागत प्रसव एवं शिशुओं के पूर्ण टिकाकरण हेतु प्रोत्साहन दिया

जा रहा है । वर्ष 2008–09 में इस योजना के अन्तर्गत 3 लाख 50 हजार महिलाओं को सम्मिलित करने का लक्ष्य है । स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सहिया कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है । सहिया का अर्थ है मित्र या संगिनी । सहिया समुदाय एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के मध्य एक सेतु का कार्य कर रही है । वर्तमान में राज्य के 59 प्रखण्डों में चलाये जा रहे इस कार्यक्रम में 27 हजार ग्राम स्वास्थ्य समितियों का गठन किया गया है एवं 41 हजार सहिया का चयन किया गया है।

कृषि के क्षेत्र में सुधार हेतु सरकार प्रयासरत है । इसके लिए वर्ष 2007–08 में वृहत एवं मध्यम सिचांई तथा लघु सिंचाई क्षेत्र से कुल 24 हजार 7 सो 65 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है । वर्ष 2008–09 में 63 हजार 4

सौ 46 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य है । इस वर्ष रामरेखा जलाशय योजना, अपरशंख जलाशय योजना, सुरंगी जलाशय योजना एवं सोनुआ जलाशय योजना को पूर्ण कर 22 हजार 69 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है । इसके अतिरिक्त लोगों में भू–गर्भ जल के दोहन से जलस्तर में निराकरण एवं प्रतिपूर्ति हेतु जागरुकता अभियान एवं वर्षा जल से भू–गर्भ जल सम्वर्द्धन हेतु सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए रुफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना जोरो से चलायी जा रही है ।

राज्य के विकास के रास्ते में आज उग्रवाद एक बड़ी समस्या है । इस समस्या से निपटने में हमें एक हद तक कामयाबी मिली है, किंतु इस दिशा में और प्रयास करना बाकी है । इसी प्रयास के तहत जहाँ एक ओर सरकार राज्य की शांति को चुनौती

दे रहे उग्रवादियों के विरुद्ध सतत् अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर उग्रवाद की ओर भटके नवयुवकों को मुख्यधारा में लाने के लिए उदार प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति पर भी कार्य कर रही है । लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है । राज्य से उग्रवाद को मिटाने के लिए सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के साथ–साथ जनसाधारण में भी परिवर्तन आवश्यक है ।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न नगर निकायों में विगत 22 वर्षों के पश्चात राँची नगर निगम एवं अधिसूचित विभिन्न 27 नगर निकायों में सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न कराया गया । सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए राँची में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करनेवाले झारखंड के शूरवीरों एवं कर्तव्य की बलिवेदी पर प्राणों की आहूति देनेवाले भारतीय सेना एवं झारखंड

पुलिस के जवानों के सम्मान एवं स्मृति में झारखंड युद्ध स्मारक का निर्माण कर रही है। सरकार द्वारा पत्रकारों के कल्याण हेतु गठित झारखंड पत्रकार कल्याण कोष में अब तक 40 लाख रुपये जमा किये गये हैं।

प्यारे झारखंडवासियों संथाल परगना प्रमण्डल की स्थिति व हालात अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम विकसित है, इसके विकास हेतु सरकार विशेषरुप से प्रयासरत है । इस क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार ने अपनी कृतसंकल्पता दिखाते हुए दुमका जिला अन्तर्गत पावरग्रीड स्टेशन, महारो का निर्माण करने का कदम उठाया गया है जो कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है । आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा । लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने हेतु दुमका जिला अन्तर्गत शहरी क्षेत्र एवं बासुकीनाथ अधिसूचित क्षेत्र में जलापूर्ति योजना प्रारंभ किये जा रही है ।

दुमका शहरी क्षेत्र अन्तर्गत स्वीकृत योजना के लिए मसानजोर डैम के बास्कीचक ग्राम को जलश्रोत के रुप में चिन्हित करते हुए इन्टैक्ट वेल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । इसके अतिरिक्त 41 करोड़ के प्राक्कलित राशि से जलशोधन यंत्र दुमका के सृष्टि पहाड़ पर निर्माणाधीन है । इससे लगभग 1 लाख की आबादी लाभान्वित होगी । साढ़े पाँच करोड़ के प्राक्कलित राशि से बासुकीनाथ अधिसूचित क्षेत्र अन्तर्गत पेयजलापूर्ति योजना प्रारम्भ की जा रही है, जिससे लगभग 15 हजार लोग लाभान्वित होंगे । इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की अलख जगाने हेतु देवघर जिला मुख्यालय के प्रशिक्षण केन्द्र में बी0आई0टी0 मेसरा का विस्तार पटल स्थापित कर अभियंत्रण की पढ़ाई प्रारंभ कर दी गयी है । ग्राम रतनपुर में 30 एकड़ भूमि में इस संस्थान की अपने भवन का निर्माण कार्य प्रग्रति पर है । आशा है कि वर्ष के अन्त तक निर्माण कार्य पूर्ण हो

जायेगी तथा आगामी सत्र में अभियंत्रण का पठन–पाठन यहाँ होगा । केन्द्र सरकार, इस क्षेत्र में रेल के विकास में अहम भूमिका का निर्वाह करते हुए देवघर–दुमका–रामपुरहाट, मंदारहिल–दुमका रेल लाईन परियोजना प्रारंम्भ करने जा रही है । इसके लिए आवश्यक भू–अर्जन के पश्चात सम्पूर्ण जमीन रेल विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है । विकास के इन प्रयासों में सरकार, जन प्रतिनिधिगण, गैर सरकारी संगठनों तथा आम जनता को मिल–जुलकर कार्य करना होगा, ताकि इस पिछड़े क्षेत्र का अपेक्षित विकास हो सके ।

अन्त में मैं एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप नये संकल्प के साथ झारखंड प्रदेश, अपने समाज और देश के विकास में जुट जायेंगे व आप अपनी कर्मठता, निश्छलता और

ईमानदारी से कार्य करेंगें, जिससे पूरे देश में आपकी मिसाल दी जाय ।

जय हिन्द ! जय झारखंड !